प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने उद्योगों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता बताई, तहसील स्तर पर भी उत्पादों का होगा चयन

एक जिला एक उत्पाद का विस्तार शामिल होंगे प्रदेश भर के स्वाद

योजना

आगरा, वरिष्ठ संवाददाता। जरूरी नहीं कि एक जनपद के एक उत्पाद को ही वरीयता की श्रेणी में रखा जाए। यदि आधा दर्जन उत्पाद भी होंगे तो उनको इस योजना में शामिल कर विस्तार किया जाएगा। बुधवार को हरीपर्वत स्थित एक होटल में उद्योग संवाद (एमएसएमई पावर टॉक 2025) के दौरान प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने यह बात रखी।

उन्होंने कहा कि आगरा ही नहीं प्रदेश भर में अनेकों स्वाद ऐसे हैं जो देश दुनिया में छा सकते हैं। तहसील स्तर पर भी उत्पादों का चयन किया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी के अंतर्गत फायदे और बढ़ाए जा रहे हैं। सब्सिडी की राशि को 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख और वित्तीय सहायता को दो करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ किया जाएगा।

वक्ताओं द्वारा आगरा में ताज संरक्षित क्षेत्र की बंदिशों की व्यथा पर बोले कि उद्योगों को अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं। प्रदेश सरकार दमदार पैरवी करेगी। निजी स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर सरकार का जोर है। स्टांप ड्यूटी में फायदा दिया जाएगा। ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन, लघु उद्योग भारती और चैंबर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के इस आयोजन में प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनाने के संकल्प को दोहराया गया। कहा कि सरकार लैंड बैंक पर काम कर रही है। इस कवायद की वजह यह है कि प्रदेश में कृषि के बाद एमएसएमई ही सर्वाधिक रोजगार सृजित करते हैं। दो करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। कार्यक्रम में ब्रश एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट एसोसिएशन को एमएसएमई विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार ने आभार व्यक्त किया। संचालन अनुज अशोक ने किया। डॉ. रंजना बंसल, राजकुमार भगत, विजय गुप्ता, अजय अग्रवाल ने विचार रखे।

काशी, अयोध्या के बाद मथुरा के विकास का नंबर

मंत्री ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की प्रशंसा की। इसमें सब्सिडी और वित्तीय सहायता के स्थानीय आंकड़े रखे। बताया कि काशी और अयोध्या के बाद मथुरा के विकास का नंबर है। विभिन्न चरणों में 50,000 करोड़ रुपये लगाया जाएगा। कानपुर में 35 हजार करोड़ लगाए जाएंगे। संयोजक मनीष अग्रवाल ने कहा कि इस मंच के संवाद से न सिर्फ उद्यम की दिक्कतें दूर होंगी। नीति निर्धारण में भी जमीनी स्तर के सुझावों का समावेश हो सकेगा। वहीं, पूरन डावर ने सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एसपीवी (स्पेशल पर्पज व्हीकल) बनाने का सुझाव दिया।

होटल होलीडे इन में बुधवार को उद्योग संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ करते एमएसएमई मंत्री राकेश सचान व अन्य।

नहीं रहेगी औद्योगिक भूमि की कमी

यूपी लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राकेश गर्ग ने उद्यमियों की भूमि संबंधी मांग पर कहा कि इसका समाधान सरकार ने दे दिया है। सात और नौ मीटर सड़क पर भी उद्योग लग सकेंगे। पहले 12 मीटर की अनिवार्यता थी। कृषि भू-उपयोग का एफएआर (फ्लोर एरिया अनुपात) 1.2 था। अब बढ़ाकर 1.5 कर दिया गया है। औद्योगिक भू-उपयोग भूमि पर 3.00 कर दिया गया है। कृषि भू-उपयोग भूमि पर ग्राउंड कवरेज 0.1 (10%) था जो अब नये नियमावली में सेटबैक छोड़कर शेष भूमि पर निर्माण अनुमोदित कर दिया गया है।

लीजेंड अवार्ड 2025 दिए गए

आरपी कंस्ट्रक्शन, अरज ड्राई फ्रूट्स, काईला इंस्ट्रूमेंटेशन, आरआरआर इंफ्रा डेवलपर, पोद्दार मिल्क प्रोडक्ट्स, चौबेजी मसाले, धीर फूड, अग्रवाल क्रोकरी, शिल्पा मसाले, कपूर मसाले इंडस्ट्रीज, बालाजी ओवरसीज के प्रतिनिधियों को लीजेंड अवार्ड 2025 दिया गया।

टीटीजेड पर निकाली भड़ास

अनेक वक्ताओं ने टीटीजेड को लेकर भड़ास निकाली। कहा कि यह आपातकाल सरीखा है जिसे आगरा के उद्योग झेल रहे। युवा पलायन करने को मजबूर है। यूपीसीडा के रखरखाव शुल्क पर भी आपत्ति रही। प्रशिक्षित कारीगरों की कमी को गारमेंट एवं चांदी पायल उद्योग द्वारा रखा गया। रॉमसंस ग्रुप के किशोर खन्ना ने औद्योगिक भूमि का लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने की मांग को रखा। नितेश अग्रवाल ने कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाए जाने की मांग रखी। अनेकों उद्योगों की तरफ से क्लस्टर विकसित करने और ओडीओपी में शामिल करने की मांग रखी गई। जरी जरदोजी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कालीन एवं ब्रश के लिए इस प्रकार की मांग रखी गई।

उद्योग संवाद कार्यक्रम में मौजूद कारोबारी।